

- (iii) Providing the basic minimum services of safe drinking water, primary health care and facilities, universal primary education, shelter, and connectivity to all in a time bound manner;
- (iv) Ensuring environmental sustainability of the development process through social mobilisation and participation of people at all levels;
- (v) Empowerment of women and socially disadvantaged groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and Minorities as agents of socio-economic change and development.

3. Due to difficult resource availability position, it has not been possible to provide fully the requirements of the social sectors. In order to fulfill the targets in a time-bound manner especially in areas like safe drinking water, primary health care, primary/elementary education etc., an Action Plan has been formulated to achieve the goal of expansion and improvement of social infrastructure. This Action Plan is being integrated with the draft Ninth Five Year Plan approved at the meetings of the internal Planning Commission and released by the then Deputy Chairman, Planning Commission on March 01, 1998. The revised draft will be placed before the National Development Council by following the due procedure in due course.

विकास परियोजनाओं को पूरा किया जाना

2567. श्री बलवन्त सिंह रामवालिया:
श्रीमती शबाना आज़मी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1997-98 के वर्ष के दौरान कुछ विकास परियोजनाओं को अंततः मार्च, 1998 तक पूरा करने का एक निर्णय लिया था,

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और कुल निर्माणाधीन परियोजनाओं का प्रतिशत कितना है,

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के अनुसार प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका, और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री राम नाईका): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की 191 परियोजनाएं जो कि कुल निर्माणाधीन परियोजनाओं का 42 प्रतिशत बनती हैं, मार्च, 1998 तक पूरी की गयी थीं।

(ग) और (घ) मार्च, 1998 तक लगभग 52 परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और अन्य परियोजनाएं विभिन्न कारणों से पूरी न की जा सकीं जैसे कि निर्माण कार्यों की उचित गति बने रहे इसे बनाए रखने में ठेकेदारों की असफलता, ठेका देने में विलंब, कार्यों की धीमी प्रगति, आयातित और देशीय वस्तुओं की आपूर्ति करने में विक्रेताओं और सप्लायरों की असफलता, भूमि के अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण तथा दूसरे निकासी पत्रों के मिलने में देरी और निधियों के अभाव।

Impact of Structural reforms

2568. DR. JAGANNATH MISHRA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any study to evaluate the impact of structural reforms on the poor people in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any such study has been made by the premier research institutions in the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLAN-